रविवारीय

प्रो. सी.सी. त्रिपाठी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी युग

आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्षों की यात्रा पर कुछ लिखने का सोचा तो इन वर्षों की संघ की अनंत सेवाएं स्मृति पटल पर अंकित हो गयी. संघ की यात्रा को चंद पेजों या पुस्तक में नहीं समेटा जा सकता उस अथाह समुद्र को सिर्फ दिल की गहराइयों से महसूस किया जा सकता हे.आरएसएस की यात्रा एक छोटे से पौधे से एक विशाल वट वृक्ष बनने तक की कहानी है, जो संगठन की दृढ़ता, समर्पण, और राष्ट्रीय सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इन सो वर्षों की अपनी यात्रा में आरएसएस ने कोविड जैसी महामारी हो या किसी भी प्रकार की आपदा स्वयंसेवक सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर पीड़ित मानवता का सहारा बने हैं.

आरएसएस के प्रारंभिक वर्ष- संघर्ष और विकास की यात्रा- विजयादशमी, 27 सितंबर 1925 - नागपुर के एक छोटे से मैदान पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने मात्र पांच बालकों के साथ एक ऐतिहासिक शाखा प्रारंभ की. डॉ. केशव बलिराम ने कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और 1910 में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें का नारा दिया. उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल राजनीतिक आंदोलन से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता. उस दिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह छोटी सी शुरुआत एक दिन विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन में परिवर्तित हो जाएगी. आज लगभग 70,000 से अधिक दैनिक शाखाओं के साथ संघ 60 देशों में सक्रिय है. डॉ. हेडगेवार ने तत्कालीन साम्प्रदायिक दंगों में हिंदुओं की दुर्दशा को देखते हुए कहा था की हिंदू समाज को संगठित करना होगा, उनमें शक्ति और आत्मबल का संचार करना होगा. यह कार्य पीढ़ियों का है, लेकिन हमें आज से ही प्रारंभ करना होगा.

1926 में नागपुर में शाखाओं की संख्या 12 हो गई, पहला गणवेश खाकी निकर और सफेद कमीज को लिया एवं 1929 मे भगवा ध्वज को संघ का प्रतीक चिह्न स्वीकार किया गया. 1931 मे पहला संघ शिक्षा वर्ग (प्रशिक्षण शिविर) नागपुर में आयोजित हुआ. 1935 मे संघ महाराष्ट्र के बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब तक विस्तारित

हुआ. मधुकर दत्तात्रेय देवरस (भाऊ साहब) 1926 में संघ से जुड़े और जीवनपर्यंत समर्पित रहे. वे 1973 से 1994 तक सरसंघचालक रहे. उनके बाद गुरुजी गोलवलकर का युग (1940-1973) तक रहा. माधव सदाशिव गोलवलकर (1906-1973), जिन्हें %गुरुजी% के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक थे. 1933 में संघ से जुड़े और 1940 में डॉ. हेडगेवार के निधन के बाद सरसंघचालक बने. गुरुजी की पुस्तक वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड (1939) और बंच ऑफ थॉट्स संघ की वैचारिक नींव बनीं. 1973 में बालसाहब देवरस तीसरे सरसंघचालक बने 1994 में प्रो. राजेंद्र सिंह (राज्जू भैया) 4वें सरसंघचालक बने. वर्ष 2000 में के. एस. सुदर्शन 5वें सरसंघचालक बने. वर्ष 2009 में श्री मोहन भागवत 6वें सरसंघचालक बने जो वर्तमान में अपना दायित्व निभा रहे हैं. .

स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का योगदान- यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (ऋस्स) ने संगठन के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन अनेक स्वयंसेवकों ने व्यक्तिगत स्तर पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई. विभाजन के समय संघ ने शरणार्थियों की सेवा कर अपनी संगठन क्षमता का परिचय दिया, जिसे सरदार पटेल ने भी सराहा. गांधीजी की हत्या के बाद 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा, जो 1949 में हटा लिया गया. इसके बाद संघ के विचारों से प्रेरित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता जुड़े. आपातकाल (1975) के दौरान संघ कार्यकर्ताओं ने भारी संघर्ष किया और 1977 में जनता पार्टी की जीत में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई. 1980 में भाजपा की स्थापना के साथ संघ का राजनीतिक प्रभाव और स्पष्ट हुआ, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पूर्व प्रचारक के नेतृत्व में दिखाई देता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक सेवा यात्रा शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और राष्ट्र निर्माण के विविध क्षेत्रों में फैली हुई है. संघ परिवार में भाजपा, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र सेविका समिति सहित कई संगठन कार्यरत हैं, जिनका उद्देश्य सेवा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित है. संघ की यात्रा में विकास, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक संरक्षण, और राष्ट्रीय एकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रत्येक स्वयंसेवक ने अपना योगदान दिया है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक रणनीति एवं विकास प्रक्रिया- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक कार्यविधि शाखा प्रणाली, स्तरीय संरचना, प्रशिक्षण शिविरों और प्रचारक व्यवस्था पर आधारित है. शाखा इसकी मूल इकाई है, जहां स्वयंसेवकों का शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास होता है. संगठन पिरामिडीय ढांचे में नगर, जिला, विभाग, प्रांत और अखिल भारतीय स्तर तक फैला है. नए कार्यकर्ताओं का निर्माण संवाद, प्रशिक्षण और विचारात्मक वर्गों के माध्यम से होता है. प्रचारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं जो संगठन विस्तार में समर्पित रहते हैं. आरएसएस सामाजिक समरसता, सेवा कार्य और भौगोलिक विस्तार की रणनीति अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है. इसका निर्णय तंत्र सामूहिक सहमति पर आधारित होता है और अनुशासन, सेवा भाव तथा राष्ट्रभक्ति इसके मूल मूल्य हैं. संघ परिवार के अंतर्गत कई संगठनों का विकास हुआ है, जिससे यह संगठन भारतीय सामाजिक जीवन का एक सशक्त आधार बन चुका है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षिक पहल- विद्या भारती का उद्भव और विकास- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्याभारती के बीच संबंध वैचारिक, संगठनात्मक और व्यावहारिक स्तर पर गहरा है. 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जबकि 1977 में स्थापित विद्याभारती शिक्षा के माध्यम से इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाती है. दोनों संगठन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा के पक्षधर हैं. संघ के स्वयंसेवक विद्याभारती के स्कूलों के संचालन, शिक्षक प्रशिक्षण और छात्र गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं. यद्यपि विद्याभारती एक स्वतंत्र शैक्षिक संस्था है, वह संघ से वैचारिक प्रेरणा लेकर शिक्षा में गुणवत्ता, समावेशिता और राष्ट्र निर्माण पर बल देती है. विद्या भारती का कार्य देश के कुल 776 जिलों में से 668 जिलों में सुचारू रूप से चल रहा है. विद्या भारती इन जिलों में 21494 औपचारिक विद्यालय एवं 9336 संस्कार केंद्रों में माध्यम से राष्ट्र के संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने एवं विद्यार्थियों के सर्वणों विकास में लगा हुआ हैं. इन विद्यालयों में 144425 शिक्षक एवं 3298925 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. विद्या भारती के अनौपचारिक शिक्षण संस्थानों में जहां सरकारी संसाधन की उपलब्धता एवं छोटे दूरवर्ती क्षेत्र के स्थानों में 234997 से ज्यादा संख्या में बालक संस्कार एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा ले रहे हैं. विद्या भारती का लक्ष्य है कि 2027 तक 40 लाख छात्रों को प्रति वर्ष शिक्षा प्रदान करना एवं राष्ट्र के लिए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना है. सेवा भारती 500 से अधिक चिकित्सालयों, हॉस्टलों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से समाज सेवा कर रही है. वनवासी कल्याण आश्रम 7,000 प्रकल्पों द्वारा 50,000 छात्रों को हॉस्टल सुविधा दे रहा है. इस संबंध को लेकर इसे भारतीय मूल्यों के संवाहक के रूप में देखा जाता है.

(लेखक एनआईटीटीटीआर भोपाल के निदेशक हैं)

आज का आरएसएस- एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की ओर

आज, आरएसएस एक विशाल संगठन है जो पूरे भारत एवं विदेशों में भी काम कर रहा है. संगठन ने अपने कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.आरएसएस की यात्रा एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे एक छोटा सा पौधा समय के साथ एक विशाल वट वृक्ष बन सकता है, जो अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता हे . आरएसएस स्वयं सेवकों ने समय समय पर युद्ध ,सुनामी,गौ-संरक्षण ,कोविड-19 राहत कार्य ,राम जन्मभूमि आंदोलन में महती भूमिका निभाई हे. 2025 में आरएसएस का शताब्दी वर्ष सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण, आत्मनिर्भरता और पारिवारिक मूल्यों पर देशव्यापी अभियान के साथ शुरू किया गया. जो निसंदेह भारत के विकसित भारत बनने की दिशा में मील का पथ्थर साबित होगा.

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आज़ादी की मांग

डॉ .ब्रह्मदीप अलूने

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे है और इस निरीह भीड़ पर पाकिस्तान की सेना ने कई लोगों को मार डाला है. दरअसल पाकिस्तान की सेना कश्मीर के बाशिंदों के उस भारतीय नारे से दहशत में है,जिसमे वे कहते है की आवाज दो हम एक है. इस नारे की आवाज के गूंजते ही लोग घरों से बाहर निकल पड़ते है. बच्चे,युवा,महिलाएं और बुजूर्ग. वे सामूहिक रूप से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगा रहे है और अपनी आज़ादी चाहते है. पाकिस्तान द्वारा अवैधानिक तरीके से कब्ज़ा किये गए कश्मीर के एक बड़े भूभाग पीओके का प्रत्येक नागरिक शरणार्थी कहा जाता है और इस प्रकार उन्हें मूल अधिकारों से दूर कर दिया गया है. बीते कई दशकों से अंतराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान पीओके में स्वायत्ता और सुशासन की बात कहता है लेकिन असल में वहां के संसाधनों को लूटकर पंजाब और सिंध ले जाया जा रहा है. पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर आज अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है. प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने यहां पर्यावरणीय संकट को और गहरा कर दिया है. 1947 में जब पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर जबरन आक्रमण किया था,तभी से इसे विकास और प्रगति के मार्ग से दूर रखा गया. संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन इसे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर कहते हैं, जो इसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है.

पीओके की सत्ता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अधीन होती है और यहां पर सैन्य अधिकारी मौज मस्ती के लिए आते है. सेना ने इस भूमि को एक गरीब और पिछड़ा इलाका बनाकर आतंकवाद का गढ़ बना दिया है. कई स्थानों पर आतंकी कैम्प बना रखे है जो महिलाओं और आम नागरिकों का शोषण करते है. असीम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी पीओके के लोग गरीबी में जीने को मजबूर है. वहीं पाकिस्तानी नेता और नौकरशाह पीओके की जमीन पर बेहतरीन जिन्दगी जीने के लिए आते है. जबकि दूसरी और भारत में कश्मीर घाटी के लोग आज़ाद है,लोकतंत्र की हवा में सांस के रहे है. भारतीय नागरिक होकर उन्हें सभी संविधानिक अधिकार प्राप्त है. यहीं कारण है की अब पीओके के बाशिंदों का गुस्सा पाकिस्तानी सरकार और सेना पर फूट पड़ा है और वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आने को मजबूर हो गए है. प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आम जनता बुनियादी आवश्यकताओं के लिए तरस रही है,जबकि नेताओं को विशेषाधिकार प्राप्त हैं. जनता की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार दमनकारी कदम उठा रही है. यह हालात न केवल मानवीय संकट की ओर इशारा करते हैं, बल्कि इस क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के गहराते संकट को भी उजागर करते हैं. इस्लामाबाद लगातार पीओके की जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखता आया है, जिसके कारण वहां असंतोष और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा.

पीओके की जनता लंबे समय से भीतरी और बाहरी संकटों से जूझ रही है. उन्हें न तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया है और न ही कल्याणकारी नीतियों का. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश और दमनकारी नीतियों ने यहां व्यापक असंतोष और जनआंदोलनों को जन्म दिया है. पाकिस्तान सरकार और सेना ने नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर उन्हें राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया है. भारत के कश्मीर में विकास,तकनीकी प्रगति, शिक्षा और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. पीओके के युवा बहुत गुस्से में है. बेहतर भविष्य की तलाश में वे यहां से पलायन करना चाहते है तथा शिक्षा,स्वास्थ्य सेवाओं तथा आधारभूत ढांचे को लेकर अपनी सरकार के प्रति उनमें गहरा असंतोष है. पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजनीतिक स्थिति बेहद जटिल और विरोधाभासी है. सतही तौर पर यह क्षेत्र एक स्वायत्त इकाई के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन व्यवहार में इसकी राजनीतिक संरचना पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता और सेना के नियंत्रण में बंधी हुई है. पाकिस्तान सरकार और सेना पर आरोप है कि उन्होंने पीओके को लोकतांत्रिक अधिकारों और आत्मनिर्णय से वंचित कर केवल एक सामरिक औजार की तरह इस्तेमाल किया है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश और विपक्षी आवाजों का दमन भी जनता के असंतोष को बढ़ा रहा है. यह आंदोलन इस बात का संकेत है कि जनता अपने अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के लिए गंभीर संघर्ष कर रही है. पीओके की जनता अब धीरे-धीरे यह समझने लगी है कि पाकिस्तान के अधीन रहकर उनकी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है. लंबे समय से वे महंगाई,बेरोजगारी,भ्रष्टाचार और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से पीड़ित हैं. जल संसाधनों और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर होने के बावजूद न तो उन्हें सस्ती बिजली मिलती है और न ही रोजगार. सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले अनेक लोग अब खुलकर यह मांग उठाने लगे हैं कि पीओके का भारत में विलय हो जिससे वे भी समान अवसर और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ आगे बढ़ सकें. स्पष्ट है कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान के झूठे वादों को समझ चूके है,पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न और दमन से ऊब चुके हैं. अब ये लोग भारत के साथ जुड़कर अपनी दशकों पुरानी समस्याओं से मुक्ति की राह देख रहे हैं.

जनरेशन बीटा बनाम कल्कि अवतार

संदीप खमेसरा

जनरेशन ज़ी जाग रही है. जनरेशन अल्फा, लगाम अपने हाथों में लेने को लगभग तैयार है. ये दोनों, विरासत में जो भूमिका जेनरेशन बीटा के लिए छोड़ कर जाएंगे, उसी में से कल्कि का उदय होगा. कल्कि, सामूहिक चेतना का ही प्रारूप होगा. कोई या कई व्यक्ति इस सामूहिक चेतना को दिशा देने का काम कर सकते हैं, जैसे द्वापर में श्रीकृष्ण ने किया था.

(1997-2010 के बीच जन्मे जनरेशन ज़ी हैं, 2010- 2024 अल्फा और 2025- 2039 बीटा)

दुनिया भर में क्रांतियां घटने जैसी आहट है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबमें युवाओं की भूमिका अहम है. कितने विनाश के बाद पुनरुथान का द्वार खुलता है, यह देखने की बात है.

- 2020 पुलिस बर्बरता के खिलाफ नाइजीरिया में.
- 2024 टैक्स और वित्तीय बिल के खिलाफ केन्या में.
- 2025 सांसदों का अप्रत्याशित वेतन बढ़ाने के बिल के खिलाफ इंडोनेशिया में.
- 2025 बिजली पानी को लेकर मेडागास्कर में.
- 2025 पेंशन सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ पेरू में.
- 2025 बाढ़ नियंत्रण में भ्रष्टाचार के विरोध में फिलीपींस में.
- 2025 भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन पर नेपाल में.

और इसी वर्ष, अब मोरक्को में फीफा 2030 के विरोध में. हॉस्पिटल और शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार के पास पैसा है नहीं और दस अरब डॉलर फीफा पर फूंकने की योजना पर काम कर रहे!

आज की पीढ़ी का दायरा अपने स्वयं के स्वार्थ के इर्दगिर्द अधिक रहता है. दूसरा, चूंकि वे स्वयं आजादी चाहते हैं और दखलअंदाजी पसंद नहीं करते, तो धीरे धीरे उनकी मानसिकता वैसी हो गई कि कुछ गलत भी हो रहा है, तो उसे नजर अंदाज किया जाए. ऐसे में गलत के प्रति उनकी कोई मजबूत प्रतिक्रिया तब तक नहीं आती, जब तक उनका कोई स्वार्थ प्रभावित न हो जाए. नेपाल में सोशल मीडिया बैन से उठी ज्वाला, फिर भ्रष्टाचार को भी घेर ले यह अलग बात है.

आने वाली पीढ़ी की सुविधा या उसकी आजादी में कोई चीज बाधक बने, तो वे तुरंत एक होकर प्रतिक्रिया देंगे. यही जागरण, जब राष्ट्र या पृथ्वी के उत्थान में अभिव्यक्ति पा ले, तो कुछ विनाश के उपरांत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है.

सोशल मीडिया किसी भी क्रांति में महत्ती भूमिका निभाएगा, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है. इस माध्यम से कोई भी आह्वान आसानी से घर घर में पहुंच जाएगा. कलयुग में कलपुर्जों से बने ये उपकरण किसी भी क्रांति के उद्घोष का सशक्त माध्यम बनेंगे.

सामूहिक चेतना सही दिशा और मानव कल्याण के लिए जागे, यह महत्वपूर्ण है. कई बार एक उद्घोष पर बिना किसी कारण के, कत्लेआम के लिए हजारों की भीड़ का इक्कठा होकर उत्पात मचा देना, खतरे की घंटी की ओर भी इंगित करता है.

बिना उद्देश्य के इक्कठी हुई बेकाबू भीड़ विनाश ही अधिक करती है. समय आ गया है, जब ऐसे इन्फ्लूएंजर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना रुतबा प्रतिष्ठित करें, जो किसी भी बड़े और सकारात्मक उद्देश्य के लिए यदि आह्वान करें, तो जयघोष के साथ लाखों युवा उनके साथ कदम से कदम मिला कर अपना योगदान दें. लेकिन दिशा एक ही रहे. स्वार्थ नहीं, देश का और इस सभ्यता का पुनरुथान!

पहलगाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की बाढ़

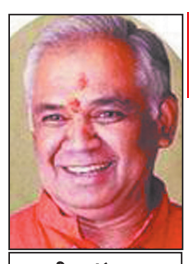

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एकतरफा जीत थी, जहां पाकिस्तान मिनमनाते, गिड़गिड़ाते हुए सैनिक कारवाई रोकने की भीख मांग रहा था. जबकि क्रिकेट का यह फाइनल मैच फाइनल (अंतिम) ओवर तक चला. आखरी एक ओवर के पहले तक मैच 50-50 था और यदि आखिरी ओवर में हम 10 रन नहीं बना पाते, जो थोड़ा मुश्किल काम था, तो हम पिद्दी न पिद्दी का शोरबा जैसे पाक़िस्तान से हार भी सकते थे. युद्ध और खेल की प्रकृति अलग होती है. एक में जीवन और सुरक्षा दाव पर होते है तो दूसरे में खेल मैदान कौशल और नजाकत. इसलिए इस मैच के परिणाम की तुलना किसी भी रूप में ऑपरेशन सिंदूर से नहीं की जा सकती है. क्योंकि जहां खिलाड़ियों से लेकर आम भारतीय जीत पर उल्लास मना रहे हो, तालियां बजा रहे हो, जैसे कि सावन के अघाए को मल्हार सूझे, दुश्मन पर वह उल्लासपूर्वक जीत की भावना शहीद परिवारों की गमगीन भावनाओं पर लेप नहीं लगा सकती हैं. उसके लिए तो हमें भी उतना ही धीर-गंभीर होकर उनके दुख-दर्द में शामिल होकर उनके ही जैसी भावनाओं में डूबना होगा. याद कीजिए! ऑपरेशन सिंदूर में भारी विजय के बावजूद भारत में विजय उत्सव प्राय नहीं मनाया गया. जबकि पाकिस्तान में भरपूर दिए जलाए गए. 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी पूर्ण लहजे में कहा; रोटी खाओ, नहीं तो गोली खाओ. इसके पूर्व पहलगाम हत्याकांड के होते ही विदेश यात्रा अधूरी छोड़कर देश वापस आकर बिहार की भूमि से हुंकार भरते हुए कहा- धरती के किसी भी कोने से ढूंढ कर आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा. प्रधानमंत्री के इन कड़क संदेशों व कार्रवाईयों ने ही उन भुक्तभोगी परिवारों के घावों पर कुछ मरहम लगाने का प्रयास अवश्य किया.

राष्ट्रवाद और अखंड भारत की प्रखर नीति के साथ आपातकाल में ध्वस्त हुए लोकतंत्र का सामना कर सुदृढ़, अखंड व विकसित भारत को बनाने में लगी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय निर्णयों की श्रृंखला से परे, हालिया दो निर्णय- भाजपा के सिद्धांतों, रीति-नीतियों व पहचान से मेल नहीं खाते हैं. एक-लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, अहिंसावादी, गांधीवादी, सामाजिक नवाचारी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी. जिन्होंने अनुच्छेद 370 के निर्णय से लेकर लगातार मोदी की प्रंशसा की हो, जो कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं. दूसरा एशियन क्रिकेट कप में पाकिस्तान के विरूद्ध प्रारंभिक हिचकिचाहट के साथ खेलना. यहां अभी मैं सिर्फ एशिया कप के संबंध में भारत की नीति का विश्लेषण कर रहा हूं.

खेलने का निर्णय आम भावनाओं के विरूद्ध- एशियाई क्रिकेट कप में जब खेलने की बात आई, तब देश में चारों तरफ यही चर्चा थी कि भारत को इस कप में भाग नहीं लेना चाहिए. कारण इसमें दुश्मन देश पाकिस्तान खेल रहा है, जिसने कुछ महीने पूर्व ही पहलगाम आतंकी क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया था. यद्यपि हमने पहले भी खेलों में पाकिस्तान का बॉयकॉट किया है. तथापि खेल को लेकर दुश्मन देश से बॉयकॉट करने की नीति सिर्फ हमारी ही नहीं रही है, बल्कि विश्व में भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर खेलों का बॉयकॉट पहले भी होता रहा है. सियोल, लॉस एंजिल्स, मास्को ओलंपिक आदि अनेकोनेक इसके उदाहरण है. चूंकि वर्तमान में भारत, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है, शायद इसलिए भारत ने एशिया कप में खेलने की नीति बनाकर उसे सही ठहरने के लिए प्रारंभिक नैरेटिव यह बनाया कि किसी तीसरे देश में (मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में) भारत पाकिस्तान के साथ खेल सकता है. यानी कि मन मन भावे मूंड हिलावे . वैसे एशिया कप का मेजबान देश मूल रूप से भारत था. इसलिए पाकिस्तान को वीजा न देने की स्थिति में भविष्य में गंभीर परिणामों को टालने की दृष्टि से भारत ने तटस्थ जगह यूएई में मैच स्थानांतरित किये.

पहलगाम हत्याकांड में 25 मासूम भारतीय, महिलाओं की आंखों के सामने गोली से भून डाले गये. इसकी कड़ी, कठोर व त्वरित प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार ने ईंट की लेनी और पत्थर की देनी नीति को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान से व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध सीमित किए, सिंधु जल समझौते पर रोक, अटारी चौकी बंद करना और पाकिस्तानी कूटनीतिक कर्मियों को निकाला. इन निर्णयों का तर्क स्पष्ट था. आर्थिक संसाधनों के उपयोग से आतंकवाद की वित्तीय सहायता रोकी जाए. साथ ही सैन्य दृष्टि से ऑपरेशन सिंदूर कर कड़ा प्रहार कर माकूल जवाब भी दिया. सरकार की यह नीति रही है आतंक/ गोली और बातचीत एक साथ संभव नहीं. खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. आतंकी कार्रवाई- बिरियानी एक साथ नहीं. सूर्य कुमार यादव कप्तान ने शाहिद अफरीदी के 'न्योते' के जवाब में उक्त बात कही.

दोहरा मापदंड?- पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध लगाते समय भारत सरकार का यह स्पष्ट मत था कि इस व्यापार से पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है, उसका उपयोग कहीं न कहीं पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में करता है. अत: क्या उक्त मापदंड क्रिकेट मैच खेलते समय भी नहीं अपनाया जाना चाहिए था? एशियन क्रिकेट कप के पाकिस्तान में आयोजन से लेकर भारत के मैच खेलने तक पाकिस्तान को लगभग 200 करोड़ से अधिक पैसा मिलेगा, उसका दुरुपयोग भी तो पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में ही करेगा? यह ऑपरेशन सिंदूर? के अखाड़े के लतख़ोर को पहलवान बनाना नहीं है तो क्या है? यह दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? खेल के दौरान हाथ न मिलाना, गले न मिलना या ट्रॉफी न लेना एक तरफ आप पाकिस्तान से विरोध की औपचारिकता को पूरा करते हुए दिखना चाहते हैं. लेकिन दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव की पीसीबी के अध्यक्ष, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष व पाकिस्तान के इंटीरियर मंत्री मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते मुस्कुराते हुए वीडियो वायरल होती है. गाल फुलाना और मुस्कुराना एक साथ संभव नहीं है. इस प्रकार आप 'खेल' खेल कर खेल की खेल भावनाओं को ही खत्म कर रहे हैं, जो खेल का अभिन्न व मूलभूत अंग तथा उद्देश्य होता है. यद्यपि यह भी एक तथ्य है कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में खेल-भावनाओं की बजाए कट्टर राष्ट्रीयता की भावनायें ज़्यादा प्रबल होती हैं. ऐसा लगता है कि गले व हाथ न मिलाकर भारत सरकार का यह नजरिया रहा है कि हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी एकलव्य खिलाडी हैं, जिनकी दृष्टि सिर्फ बॉल व बेट पर ही केंद्रित रहेगी, दुश्मन खिलाडियों पर नहीं. क्योंकि हमारे खिलाड़ी तो उसका चेहरा देखना पसंद ही नहीं करते है? इस पूरे एपिसोड़ को एक मुहावरे गुड़ खाए गुलगुले से परहेज में समेटा जा सकता है. इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार हमारी सरकार की नीति तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बावजूद इसके इस स्लोगन के साथ नियमानुसार इसका उत्पादन कर बेचा जा सकता है. उसके उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं? ठीक इसी प्रकार की मानसिक स्थिति भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खेलते समय अपनायी. खेलेगें, लेकिन दुश्मनी तथाकथित रूप से दिखाकर.

इतिहास से सबक क्यों नहीं?- वैसे तो क्रिकेट को जैंटलमेन खेलसी कहा जाता है. बावजूद इसके सर्वप्रथम वर्ष 1986 में श्रीलंका में हो रहे एशिया कप का श्रीलंका के साथ चले राजनैतिक तनाव के कारण भारत ने बॉयकॉट किया गया. तत्पश्चात पाकिस्तान के 1990-91 के एशिया कप को बॉयकॉट करने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट बंद हो गया था. इस तनाव की वजह से 1993 में होने वाले एशिया कप को रद्द तक किया जा चुका है. 2008 के मुम्बई हमले के बाद भारत ने द्विपक्षीय सीरीज को पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था. तब फिर आज एक मजबूत सरकार के रहते क्रिकेट खेलने के लिए हम मजबूर क्यों हुए? यह अनुत्तरित प्रश्न उन शहीद परिवार के घावों को ताजा करने वाला है, भरने वाला तो कदापि नहीं. एक भारतीय के मन में भी क्रिकेट के टॉस की यही टीस है. व्यक्ति की एक सामान्य कमजोरी होती है कि वह सामान्यत: तब तक ही ईमानदार रहता है, जब तक कि रिश्वत का ऑफर नहीं मिलता, और ऑफर मिले तो पसेरी वाली भी दुह लेता है और पाव वाली भी. ठीक उसी प्रकार यदि क्रिकेट मैच टीवी पर नहीं दिखाया जाता, तो शायद आम भारतीय भी मैच देखने की मांग नहीं करते.